चुनावी बॉन्ड पर भ्रम फैला रहा विपक्ष: मोदी

एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर लगाए कई आरोप

अर्चिस मोहन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों की भूमिका को ज्यादा अहम बताते हुए संकेत दिया है कि भविष्य में देश का आर्थिक एजेंडा आगे बढ़ाने का काम राज्य ही करेंगे। उन्होंने कहा कि लोक सभा चुनाव संपन्न होने के बाद अगली सरकार नीति आयोग की बैठक में आने वाले पांच साल के लिए कामकाज का अपना दस्तावेज राज्यों के साथ साझा करेगी।

समाचार एजेंसी एएनआई ने मोदी का साक्षात्कार किया था, जिसे आज शाम प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर वेबकास्ट किया गया। साक्षात्कार में मोदी ने चुनावी बॉन्ड योजना, भ्रष्टाचारियों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई और कांग्रेस के घोषणापत्र समेत कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष का घोषणापत्र लागू हो गया तो वह देश की अर्थव्यवस्था को 'रौंद' देगा।चुनावी बॉन्ड पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, वे जब ईमानदारी से अपने भीतर झांकेंगे तो अफसोस करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्डों के जरिये 3,000 कंपनियों ने राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया, जिनमें से 26 पर जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की है। उनमें से भी 16 कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को चंदा दिया, जो जांच के दायरे में आई सभी कंपनियों द्वारा दिए गए कुल चंदे का 37 फीसदी ही है। बाकी 63 फीसदी रकम विपक्षी दलों को मिली है।

उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं और आलोचकों के दावों के उलट चुनावी बॉन्ड योजना चुनावों में काले धन का बोलबाला कम करने की दिशा में उठाया गया कदम थी। मोदी ने कहा, 'यह चुनावी बॉन्डों की सफलता है। चुनावी बॉन्ड थे, इसलिए आपको पता चल रहा है कि किस कंपनी ने चंदा दिया, कितना दिया और किसे दिया। इस पूरी प्रक्रिया में अच्छा हुआ या बुरा हुआ, इस पर बहस हो सकती है... मैं कभी नहीं कहता कि निर्णय लेने में खामी नहीं होती। हम बातचीत करने और सुधार करने के बाद सीखते हैं। इसमें भी सुधार की बहुत गुंजाइश है। मगर आज हमने देश को पूरी तरह काले धन की ओर धकेल दिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि हर किसी को इस पर अफसोस होगा। ईमानदारी से सोचने पर हर कोई इस पर अफसोस करेगा।'

उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि इसे खत्म करना चुनावों के दौरान देश को 'काले धन' की ओर ले जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नोटबंदी ने चुनावों में बेनामी पैसे के इस्तेमाल पर लगाम लगाई। प्रधानमंत्री ने कहा, 'चुनावों के दौरान 1,000 और 2,000 रुपये के नोट बड़ी तादाद में इस्तेमाल होते थे। हमने कदम उठाया ताकि काले धन का खात्मा हो सके।' उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड पेश करने के पीछे उनकी सरकार की मंशा एकदम सही थी। मोदी ने कहा, 'हम कोई रास्ता तलाश कर रहे थे। हमें एक छोटा रास्ता नजर आया। हमने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को तमिलनाडु में चुनावी सभा को संबोधित किया

कभी यह दावा नहीं किया कि यही इकलौता रास्ता है।'

यह कहे जाने पर कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 400 से अधिक सीट मिलने को लेकर लोगों का एक धड़ा चिंतित है, प्रधानमंत्री ने कहा कि वह लोगों पर दबाव बनाने या उन्हें डराने के लिए निर्णय नहीं लेते। उन्होंने कहा, 'जब मैं कहता हूं कि हमारे पास भविष्य के लिए बड़ी योजनाएं हैं, तो इससे किसी को भयभीत होने की आशंका नहीं है। मैं लोगों को डराने के लिए निर्णय नहीं लेता हूं। मेरे निर्णय देश के समग्र विकास के लिए हैं।' प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारें जहां दावा करती थीं कि उन्होंने हर जरूरी काम कर दिया है वहीं उन्हें महसूस होता है कि काफी कुछ किया जाना बाकी है। मोदी ने कहा कि इसी वजह से उन्होंने कहा था कि अब तक जो हुआ है वह महज एक झांकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2019 के चुनाव के पहले भी उन्होंने 100 दिन का एजेंडा बनाया था। उसी के चलते उनकी सरकार कार्यकाल के पहले 100 दिनों के भीतर अनुच्छेद 370 हटाने तथा अन्य कानूनों में संशोधन करने में कामयाब हो सकी। मोदी ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके अनुभव ने उन्हें सिखाया कि 40-50 दिनों के लिए वरिष्ठ अधिकारी चुनाव में लगे रहते और सरकार का कामकाज प्रभावित होता। उन्होंने कहा कि चुनावी अवधि को 'छुट्टियों' की तरह नहीं बिताया जाना चाहिए और वह अधिकारियों को पहले ही ऐसे काम दे देते थे जिन्हें अगली सरकार को करना होता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने 100 दिन, पांच वर्ष और 25 वर्ष के लिए एजेंडे तैयार किए हैं। ये भाजपा के चुनावी घोषणापत्र तथा नमो ऐप पर 15 लाख लोगों द्वारा दिए गए सुझावों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि वह चुनाव के बाद नीति आयोग की बैठक में उसे राज्य सरकारों के साथ साझा करेंगे।

मोदी ने कहा, 'मैं बीते दो वर्ष से 2047 की योजना पर काम कर रहा हूं। उसके लिए मैंने देश भर के लोगों से सुझाव और विचार आमंत्रित किए। मैंने 15 लाख से अधिक लोगों से यह राय ली कि वे अगले 15 वर्षों में कैसा देश चाहते हैं। मैंने विश्वविद्यालयों से संपर्क किया, मैंने विभिन्न एनजीओ से संपर्क किया और 15-20 लाख लोगों ने अपनी राय दी।' उन्होंने कहा, 'इसके बाद मैंने एआई की मदद से इन मशविरों को विषयवार वर्गीकृत किया। मैंने हर विभाग में अधिकारियों की टीम बनाई जो इस पर काम कर सके। यह अगले कार्यकाल के लिए कैसे हो सकता है? मैं उनके साथ बैठा और उन्होंने ढाई घंटे की प्रस्तुतियां दीं।'

भारतीयों की रिहाई के लिए ईरान से बात

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि भारत ने ईरानी सैनिकों द्वारा जब्त किए गए पुर्तगाली मालवाहक जहाज पर सवार 17 भारतीयों को रिहा करने का ईरान से आग्रह किया है और तेहरान ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास और ईरानी अधिकारियों के बीच कुछ बातचीत हुई है। जयशंकर ने कहा, 'रविवार रात, मैंने ईरान के विदेश मंत्री (हुसैन अमीर-अब्दुल्लाहियन) से बात की। मैंने उनसे कहा कि चालक दल के 17 सदस्य भारत से हैं। हमने ईरान सरकार से कहा कि इन लोगों को रिहा किया जाना चाहिए, उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए।'

जयशंकर ने कहा, 'मुझे कुछ रिपोर्ट मिल रही है लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे दूतावास के लोग वहां

एस जयशंकर, विदेश मंत्री

जाएं और इन लोगों से मुलाकात करें।' उन्होंने कहा, 'साथ ही, मैं लोगों के शीघ्रता से भारत वापस आने पर जोर दूंगा क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री का रुख सकारात्मक है। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसे समझता हूं। मैं कोशिश करूंगा और सचमुच में कुछ अच्छा करूंगा।'

चालक दल से जल्द मिल सकेंगे भारतीय अधिकारी

ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर-अब्दुल्लाहियन ने कहा है कि उनका देश भारतीय अधिकारियों को उस मालवाहक जहाज के चालक दल के 17 भारतीय सदस्यों से मिलने की अनुमति देगा, जिसे ईरान की सेना ने शनिवार को होर्मुज जलडमरूमध्य के निकट अपने कब्जे में ले लिया था। ईरान की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, अमीर-अब्दुल्लाहियन ने रविवार को टेलीफोन पर बातचीत के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर को यह जानकारी दी। इस बातचीत में जयशंकर ने पुर्तगाली झंडे वाले मालवाहक जहाज एमएससी एरीज पर सवार चालक दल के भारतीय सदस्यों को रिहा करने के लिए कहा था। **भाषा**

कारोबारी धारणा के लिए अच्छा संकेत भाजपा का घोषणा पत्र

राघव अग्रवाल

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा रविवार को जारी चुनावी घोषणा पत्र नीतिगत निरंतरता पर केंद्रित है और यह देश में कारोबारी धारणा के लिए अच्छा संकेत हो सकता है और निजी कंपनियों के पूंजीगत व्यय में भी सुधार ला सकता है। यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया के अर्थशास्त्रियों ने सोमवार को एक नोट में ऐसा कहा है। साथ ही कहा है कि कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र लोकलुभावन है।

यूबीएस की मुख्य भारतीय अर्थशास्त्री तन्वी गुप्ता और एसोसिएट अर्थशास्त्री निहाल कुमार ने कहा है, 'भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र बहुत हद तक नीतिगत निरंतरता पर केंद्रित है और पिछले 10 वर्षों से सत्ता में रहने के दौरान उनकी सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया गया है।' दोनों अर्थशास्त्रियों ने विल मोदी विन? इलेक्शन मैनिफेस्टोः पॉलिसी कंटीन्यूटी वर्सेज पॉपुलिज्म शीर्षक से नोट लिखा है। उन्होंने कहा है, 'हमारा मानना है कि नीतिगत निरंतरता पर ध्यान देना कारोबारी धारणा और निजी कंपनियों की पूंजीगत व्यय में सुधार के लिए अच्छा हो सकता है।' भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार के बारे में कहा गया है। इनमें 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, पाइप रसोई गैस कनेक्शन, अगले पांच वर्षों तक के लिए मुफ्त खाद्यान्न और गरीब तबके के लोगों के लिए मुफ्त बिजली सहित कई योजनाओं के विस्तार की बात कही गई है। साथ ही इसमें उच्च बुनियादी ढांचे के खर्च, विनिर्माण को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने सहित व्यापक सरकारी प्रयासों के बारे में भी उल्लेख किया गया है।

इससे पहले सिटी अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में बड़े पैमाने पर संरचनात्मक आर्थिक सुधारों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मगर उन्होंने कहा था कि निजीकरण, भूमि सुधार और विदेशी निवेश जैसे सुधारों की घोषणा बाद में की जा सकती है। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के बारे में यूबीएस के नोट में कहा गया है कि विपक्षी पार्टी के वादों से राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है, जिसे भाजपा ने वित्त वर्ष 2025 के अपने अंतरिम बजट में 5.1 फीसदी का अनुमान लगाया था। इसने कहा है, 'हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए लोकलुभावन वादों के क्रियान्वयन से राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 7 से 8.5 फीसदी तक बढ़ सकता है जबकि केंद्र की भाजपा सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के अपने अंतरिम बजट में इसे जीडीपी के 5.1 फीसदी के करीब रहने का अनुमान लगाया है।'

नोट में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस के चुनावी वादों को लागू करने से जीडीपी का 2 से 3.3 फीसदी की अतिरिक्त राजकोषीय लागत आएगी।

'गारंटी झूठी, लोगों को नहीं मिले 15 लाख'

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गईं गारंटी 'झूठी' हैं, क्योंकि उनमें से कोई भी पूरी नहीं हुई है। कांग्रेस के पुदुच्चेरी लोक सभा सीट से उम्मीदवार वी वैथिलिंगम के समर्थन में 'इंडिया' गठबंधन द्वारा आयोजित चुनावी रैली को संबोधित करते हुए खरगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को प्रति वर्ष दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन यह पूरा

नहीं हुआ। खरगे ने कहा, 'इसी तरह, किसानों को उनकी उपज की कीमतों में बढ़ोतरी या उनकी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। विदेश में जमा काले धन की वापसी से प्रत्येक व्यक्ति को 15 लाख रुपये मिलने का वादा भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है।' कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ऐसी गारंटी या वादे 'झूठे' थे और लोगों को 'धोखा दिया गया'। उन्होंने कहा कि इस बार का लोक सभा चुनाव लोगों के लिए 'इंडिया' गठबंधन का समर्थन करने और 'उनके मौलिक अधिकारों एवं लोकतंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने' का अवसर होगा। **भाषा**

मोदी के खिलाफ आयोग से शिकायत

कर्नाटक में कांग्रेस ने सोमवार को निर्वाचन आयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस टिप्पणी के लिए शिकायत की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को 'टुकड़े-टुकड़े गिरोह का सुल्तान' कहा था। रविवार को मैसूरु में एक विशाल जन सभा को संबोधित करते हुए, मोदी ने कांग्रेस को 'टुकड़े-टुकड़े गिरोह का सुल्तान' कहा था और विपक्षी दल पर देश को 'बांटने, तोड़ने और कमजोर करने' के खतरनाक इरादे रखने का आरोप लगाया था। **भाषा**

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
Hamesha Aapke Liye
www.bankofbaroda.in

निविदा सूचना

बैंक ऑफ़ बड़ौदा वित्तीय वर्ष 2024-27 के लिए साउंड बॉक्स उपकरणों (यूपीआई क्यूआर) की आपूर्ति, इन्स्टालेशन और रखरखाव के लिए वेंडरों को सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध आमंत्रित करता है।

विस्तृत विवरण बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in के निविदा खंड के तहत उपलब्ध है। ''अन्य सूचना'', यदि कोई हो, को बैंक की वेबसाइट पर www.bankofbaroda.in निविदा खंड में जारी किया जाएगा। प्रस्ताव को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले बोलीकर्ता इसे अवश्य देख लें।

बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 13 मई, 2024 है।

स्थान : वडोदरा
दिनांक : 16.04.2024

मुख्य महाप्रबंधक
(डिजिटल चैनल एवं परिचालन)

4/24-25

आयोग ने की अभी तक की बड़ी जब्ती

वसुधा मुखर्जी

निर्वाचन आयोग ने सोमवार को कहा कि प्रवर्तन एजेंसियों ने 4,658.16 करोड़ रुपये मूल्य के नशीले पदार्थ, शराब, नकद, बहुमूल्य धातु एवं मतदाताओं को लुभाने वाली अन्य वस्तुएं जब्त की हैं। 1 मार्च से लेकर अब तक पिछले 45 दिनों के भीतर रोजाना औसतन 100 करोड़ रुपये की जब्ती की गई है। यह पिछले लोक सभा चुनाव के दौरान कुल 3,475 करोड़ रुपये से अधिक की जब्ती से 34 फीसदी अधिक है और पिछले 75 वर्षों में सर्वाधिक है।

निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, सबसे चिंतनीय है कि 2,068.85 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं, जिनकी कुल जब्ती में 45 फीसदी हिस्सेदारी है। एजेंसियों ने 2,068.85 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की हैं, जबकि साल 2019 में 1,279.9 करोड़ रुपये की जब्त की गई थीं और जब्त किए गए मुफ्त सामान का मूल्य 1,142.19 करोड़ रुपये है, जो साल 2019 में 60.15 करोड़ रुपये था।

मार्च में चुनावों की आधिकारिक घोषणा से पहले जनवरी और फरवरी के दौरान 7,502 करोड़ रुपये की जब्ती की गई थी। निर्वाचन आयोग ने कहा कि नशीली दवाओं की बरामदगी पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया था, जो जनवरी और फरवरी में कुल बरामदगी का 75 फीसदी था। निर्वाचन आयोग ने कहा कि जनवरी से लेकर अब तक कुल 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक की जब्ती की गई है।

अब तक करीब 395.5 करोड़ रुपये नकद जब्त किए जा चुके हैं। साल 2019 के लोक सभा चुनावों के दौरान एजेंसियों ने कुल 844 करोड़ रुपये नकद जब्त किए थे। आयोग ने कहा, 'लोक सभा चुनावों को प्रलोभन और कदाचार मुक्त कराने के निर्वाचन आयोग के संकल्प में नकदी जब्त करना एक जरूरी कदम है। प्रलोभन मुक्त चुनाव कराना के लिए कड़ाई, निगरानी और जांच पर अधिक विचार-विमर्श किया जाता है।'

अधिकारियों ने राहुल गांधी को नीलगिरि पहुंचाने वाले हेलिकॉप्टर की जांच की

चुनावी जब्ती

अब तक प्रवर्तन एजेंसियों ने **4,658.16** करोड़ रुपये मूल्य की चीजें जब्त कीं, पिछले लोक सभा चुनावों के दौरान कुल **3,475** करोड़ रुपये मूल्य के सामान जब्त किए गए थे

पिछले **45** दिनों के भीतर रोजाना औसतन **100** करोड़ रुपये की जब्ती की गई

अब तक 35 करोड़ लीटर से अधिक की शराब जब्त की गई है, जिसका मूल्य 489.3 करोड़ रुपये है। पिछली बार लोक सभा चुनावों के दौरान 304.6 करोड़ रुपये मूल्य की शराब जब्त की गई थी। एजेंसियों ने 562.1 करोड़ रुपये की बहुमूल्य धातुएं जब्त की हैं, जबकि साल 2019 में जब्त की गई बहुमूल्य धातुओं की कीमत 987.11 करोड़ रुपये आंकी गई थी।

राज्यवार आंकड़ों पर गौर करें तो 13 अप्रैल तक राजस्थान से सर्वाधिक 778.5 करोड़ रुपये की जब्ती की गई है। उसके बाद गुजरात 605.33 करोड़ रुपये, तमिलनाडु 460.8 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र 431.3 करोड़ रुपये और पंजाब 311.8 करोड़ रुपये का स्थान है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से करीब 236 करोड़ रुपये की वस्तुएं और नकदी जब्त की गई है।

निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसने कर्तव्य में ढिलाई बरतने और तमिलनाडु के नीलगिरि निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रमुख नेता के काफिले की जांच में कोताही करने वाली उड़न दस्ता दल के प्रमुख को निलंबित कर दिया है। उसने कहा, 'इसी तरह अधिकारियों ने एक राज्य के मुख्यमंत्री के काफिले में वाहनों की जांच की और दूसरे राज्य के उप मुख्यमंत्री के वाहन की भी जांच की है।' साथ ही कहा गया है कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार में नेताओं की सहायता करने वाले और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के दोषी पाए गए 106 सरकारी अधिकारियों पर गाज गिरी है।

निर्वाचन आयोग ने सूत्रों ने यह भी बताया कि हेलीकॉप्टरों की जांच में कुछ भी नया नहीं है। इसी तरह की जांच तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी के हेलीकॉप्टर की भी की गई थी। चुनावों से पहले सभी जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को हवाई क्षेत्रों और हेली पैडों की कड़ी निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस तरह की तलाशी देश भर में सरकारी और निजी दोनों हवाई क्षेत्रों में की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी प्रलोभन सामग्री हवाई मार्ग के जरिये भी नहीं लाई जा सके।

निर्वाचन आयोग की सहायता करने वाली एजेंसियों में आयकर विभाग, राज्य पुलिस, भारतीय रिजर्व बैंक, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, डाक विभाग, राज्य उत्पाद शुल्क, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल और अन्य शामिल हैं।

BSmart
Case Study Challenge

Calling all the future leaders!
Dive into a real-world business challenge and stand a chance to win big.

Case Study
Evaluating Zomato's Marketing Strategy

Last day to submit your entry

Rewards

1st Prize ₹5,000
2nd Prize ₹3,000
3rd Prize ₹2,000

• Top 3 winners to be featured on the BSmart Platform
• Certificate to all eligible participants

For more information, write to campus.talk@bsmail.in

Follow us on bit.ly/bsmartchannel

Terms and Conditions applied

Meet the Winners February Case Study

1st YASHNA SHANKER
Managment Development Institute
Gurgram, Haryana

2nd DINESH KESHAVAN R
Kumaraguru College of Technology Business School
Coimbatore, Tamil Nadu

3rd ALUGOLU SWATHI BHARGAVI
Sri Ramchandra Faculty of Management Sciences
Chennai, Tamil Nadu

Business 50 Standard
Years of Insight

businessstandard bsindia business.standard business-standard.com